



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई विल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8, 1977/आश्विन 16, 1899

No. 41]

NEW DELHI, SATURDAY OCTOBER 8, 1977/ASVINA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन में रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संचरण और प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत इनाएँ और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपचिह्न आदि सम्मिलित हैं।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1977

सां. का० नं० 1319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम 1972 में (जिसे उसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. प्रतिशारक फीस और अंत :—(1) नियम 5 में वर्णित करनेवालों के अनुदालन के लिए, किसी विधि अधिकारी को निम्नलिखित संदर्भ किया जाएगा—

(क) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिशारण फीस,

(i) भारत के महान्यायवादी के मामले में, प्रतिमास चार हजार रुपये;

(ii) भारत के महासालिस्टर के मामले में, प्रतिमास तीन हजार और पाँच सौ रुपये; और

(iii) भारत के अपर भारासालिस्टर के मामले में, प्रति मास तीन हजार रुपये।

(ख) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिमास एक सौ रुपये कार्यालय-भत्ता।

(ग) उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने और अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित माप-मान के अनुसार फीस; अर्थात् :

(i) वाद, रिट यानिकाएं, अपीलें और अनुच्छेद प्रति मामला प्रतिदिन 143 के अधीन निर्देश 800 रु

(ii) विशेष इजाजत याचिकाएं और अन्य आवेदन प्रति मामला प्रतिदिन 600 रु

(iii) अभिवचनों का (जिसमें शपथ पत्र भी है) तय प्रति अभिवचन करना 400 रु

(iv) मामलों का कथन तय करना प्रति मामला 600 रु

स्पष्टीकरण :—यदि दो या अधिक ऐसे मामले, जिनमें सारतः समरूप प्रबन्ध अन्तर्भूति हो, एक से तकों के साथ सम्मिलित रूप से मुने जाते हैं तो विधि अधिकारी एक मामले के रूप के बत एक ही फीस का हकदार होगा;

(घ) किसी उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने के सम्बन्ध में, मूल्यालय से उसकी अनुस्थिति के दिनों के लिए,

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1977

सांकेतिकि० 1358.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्परा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भाकाणवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एकद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ग्रन्ति:—

1. (1) इन नियमों को भाकाणवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रभृत होंगे।

2. भाकाणवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, संयुक्त निदेशक (परिवार नियोजन) के पद से सम्बन्धित कम संख्या 9 के सम्मुख कालम 2 के अंतर्गत प्रविष्टि में “(परिवार नियोजन)” कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर “परिवार कल्याण” कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 12019/7/77-सो (ए)]
एम.एल.टंडन, प्रबन्ध सचिव

देल चिकित्सा
(देलवे बोर्ड)
नयी दिल्ली, 16 सितम्बर, 1977

सांकेतिकि० 1359.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्परा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय देल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी II) भर्ती नियम, 1967 का अधिकरण करते हुए राष्ट्रपति एकद्वारा भारतीय देल चिकित्सा सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रन्ति:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये नियम भारतीय देल चिकित्सा सेवा (सहायक चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 कहानायेंगे।

(2) ये नियम 16 अक्टूबर, 1978 से सार्व समझे जायेंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमात्र—उपर्युक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमात्र यह होगा जो इन नियमों के माध्यम संबन्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनियिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और वार्षिक वेतन—उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा वार्षिक वेतन वह होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनियिष्ट की जायेंगी।

किन्तु यह है कि उल्लिखित अनुसूची के कालम 6 में विनियिष्ट सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सुधा अन्य विवेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार कुट दी जा सकती है।

4. अनदृता:—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो जिसकी पत्नी/जिसका पति, जीवित हो अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह है कि यदि केंद्रीय सरकार यदि इस बात से अनुसृष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह किसी व्यक्ति तथा विवाह के बूसरे पक्ष पर सार्व स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट के सकती है।

5. रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व—उल्लिखित पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का, यदि अपेक्षित हो तो किसी रक्षा सेवा अथवा सारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर, प्रशिक्षण पर लगाये गये समय, यदि कोई हो तो, उसके सहित चार वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए सेवा करने का वायिक्त होगा किन्तु यह है कि ऐसे व्यक्ति के लिए—

(क) ऐसी नियुक्ति की तारीख से बस वर्ष बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) पैतासीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद उपरोक्त प्रकार की सेवा करना साधारणतया अपेक्षित नहीं होगा।

6. नियम शिखित करने की व्यक्ति—यदि केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना साधारण या समीक्षित हो तो वह किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में भादेश द्वारा लिखित रूप में कारण वर्ज करते हुए संश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपरान्ध को शिखित कर सकती है।

7. संगणनीय सेवा—जो व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत ऐसे वर्षों पर भर्ती किये जायें और जिन पर भारतीय देल स्पापना सहिता के नियम 2423-के (सांकेतिकि० 404-ए) में निर्धारित वर्ष लागू होती हो, वे उक्त नियम के उपरान्धों के लाभ के पात्र होंगे।

8. अपवाह—इन नियमों के उपरान्धों का इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विवेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले भारकाणों सुधा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 15th September, 1977

G.S.R. 1358.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, against serial number 9, relating to the post of Joint Director (Family Planning) in the entry in column 2, for the brackets and words “(Family Planning)” the brackets and words “(Family Welfare)” shall be substituted.

[No. 12019/7/77-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.